



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 211-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 4, 2023 (AGRAHAYANA 13, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 दिसम्बर, 2023

संख्या 21/2/2014-1टी(II).— मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग (नियामक विंग), अधिसूचना संख्या 21/2/2014-1टी(II), दिनांक 18 अक्टूबर, 2023, के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ये नियम हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि (संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2018 में, नियम 8 में, उप-नियम (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
 - “(2) प्रशासनिक सचिव, परिवहन विभाग प्रत्येक मामले में अधिकतम पचास लाख रूपए के अध्यक्षीन नियमों में वर्णित किसी भी प्रयोजन (आवर्ती या गैर-आवर्ती) के लिए व्यय स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत होगा।
 - (3) सदस्य सचिव प्रत्येक मामले में अधिकतम दस लाख रूपये के अध्यक्षीन नियमों में वर्णित किसी भी प्रयोजन (आवर्ती या गैर-आवर्ती) के लिए व्यय स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत होगा।”।

नवदीप सिंह विर्क,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TRANSPORT DEPARTMENT****Notification**

The 4th December, 2023

No. 21/2/2014-1T(II).— In exercise of the powers conferred by section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and with reference to the Haryana Government, Transport Department (Regulatory Wing), notification No. 21/2/2014-1T(II), dated the 18th October, 2023, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Road Safety Fund Rules, 2018, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Road Safety Fund (Amendment) Rules, 2023.
2. In the Haryana Road Safety Fund Rule, 2018, in rule 8, for sub-rule 2 and 3, the following sub-rules shall be substituted, namely:-
 - “(2) The Administrative Secretary, Transport Department shall be authorised to sanction expenditure on any of the purpose (recurring and non-recurring) mentioned in the rules subject to maximum of fifty lakh rupees in each case.
 - (3) The Member Secretary shall be authorised to sanction expenditure on any of the purpose (recurring and non-recurring) mentioned in the rules subject to maximum of ten lakh rupees in each case.”

NAVDEEP SINGH VIRK,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.